



GST के 8 वर्ष

प्रलिम्स के लिये:

[माल और सेवा कर \(GST\)](#), [अप्रत्यक्ष कर प्रणाली](#), [ई-वे बलि](#), [MSME](#), [कैसकेडिंग प्रभाव](#), [इनपुट टैक्स क्रेडिट \(ITC\)](#), [VAT](#), [GST अपीलीय न्यायाधिकरण \(GSTAT\)](#), [GST परिषद](#), [उत्कर्मि शुल्क संरचना](#), [GST नेटवर्क \(GSTN\)](#), [ICEGATE](#), [कार्बन क्रेडिट](#)

मेन्स के लिये:

गत 8 वर्षों में GST का नषिपादन और संबंधित चुनौतियाँ, मौजूदा GST ढाँचे के सुदृढीकरण हेतु आवश्यक उपाय

[स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स](#)

चर्चा में क्यों?

[माल और सेवा कर \(GST\)](#) के 1 जुलाई 2017 को लागू होने के 8 वर्ष पूर्ण होने पर, विशेषज्ञ कर एकीकरण और डिजिटलीकरण में इसकी सफलता को स्वीकार करते हैं और साथ ही सरलीकरण, दरों को युक्तिसंगत बनाने और अनुपालन भार में कमी लाने की आवश्यकता पर बल देते हैं।

वर्गित 8 वर्षों में GST की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं?

- राजस्व में रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि: GST राजस्व में नरितर वृद्धि हुई है, जो औसत मासिक संग्रह 1.84 लाख करोड़ रुपए के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में उच्चतम सकल संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
 - यह वृद्धि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक हो गई है, जो बेहतर अनुपालन, कर चोरी में कमी और आर्थिक औपचारिकता में हुए सुधार को परलिकषति करती है।
- डिजिटल परिवर्तन और अनुपालन दक्षता: GST का डिजिटलीकरण किया गया है जिसमें मैनूअल फाइलिंग से लेकर [ई-इनवाइसिंग](#), [रयिल-टाइम क्रेडिट मलान](#), [स्वचालित रटिर्न](#) और [ई-वे बलि](#) जैसी सुविधाएँ शामिल हैं जिससे त्रुटियों और धोखाधड़ी की संभावना कम हो गई है।
 - पूर्व में [MSME](#) इसको लेकर संशय में थे कति वर्तमान में इसे ऋण, सरकारी खरीद और राष्ट्रीय बाज़ार के अभगिम का प्रवेश द्वार मानते हैं।
- वसितारति करदाता आधार: 30 अप्रैल, 2025 तक भारत में 1.51 करोड़ से अधिक सक्रिय GST पंजीकरण दर्ज थे जो वर्ष 2017 के 65 लाख पंजीकरण में हुई उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
 - यह वृद्धि अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण करने और कर अनुपालन में सुधार लाने में GST की सफलता को रेखांकित करती है।
- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस: GST से अंतर-राज्यीय कर बाधाएँ समाप्त हुईं, रसद लागत में कमी आई और आपूर्ति शृंखला दक्षता का वर्द्धन हुआ, जबकि प्रवेश करों और चुंगी (Octroi) की समाप्ति से व्यापार लागत में और अधिक बचत हुई है।
 - GST के 'एक राष्ट्र, एक कर' ढाँचे के माध्यम से बहुस्तरीय कर प्रणाली को प्रतस्थापति किया गया, जिससे [कैसकेडिंग प्रभाव](#) कम हो गया, जबकि [इनपुट टैक्स क्रेडिट \(ITC\)](#) तंत्र से नरिबाध ऋण प्रवाह सुनिश्चित हुआ, व्यापार लागत में कमी आई और प्रतसिपर्द्धा को बढ़ावा मिला।
- कुशल रफिंड प्रसंसकरण: सीमा शुल्क ICEGATE पोर्टल के माध्यम से स्वचालित एकीकृत GST (IGST) रफिंड प्रसंसकरण में तेज़ी आई है और रफिंड की प्रक्रिया अब केवल एक सप्ताह का समय लगता है। वित्त वर्ष 2025 में 1.18 लाख करोड़ रुपए का संवतिरण किया गया, जिससे नरियातकों की चलनधि में वृद्धि हुई।

माल एवं सेवा कर (GST) क्या है?

- GST: 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से अनेक केंद्रीय और राज्य करों को GST के अंतर्गत शामिल कर समग्र भारत में एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरुआत की गई।
 - GST सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर अधरिपति मूल्य-योजति कर (Value-Added Tax) है।

- इसने उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे केंद्रीय करों तथा VAT, केंद्रीय बिक्री कर एवं वलासिता कर जैसे राज्य करों का स्थान लिया।

Timeline

2006-07: The govt moots a proposal for GST in the Budget; negotiations with states begin

2008: The govt. constitutes the empowered committee (EC) of state finance ministers

2009: The committee releases its first discussion paper

2011: The UPA govt. introduces the Constitution Amendment Bill for GST in Lok Sabha (LS)

Aug 2013: The Parliamentary Standing Committee submits its report; the govt incorporates recommendations of the committee in the Bill

Sep. 2013: Revised bill sent to the empowered committee

Dec 2014: The Constitution Amendment Bill introduced in the LS

May 2015: LS passes the Bill

August 2015: Congress insists on

capping GST rate at 18%, and specifying the same in the Constitution Amendment Bill

July 2016: The Centre and states agree against capping GST rate in the Constitution Amendment Bill

Aug 2016: Rajya Sabha passes Constitution Amendment Bill Industry hails reforms, says will make doing business easier

मुख्य वशिषताएँ:

- **आपूर्ति-आधारित कराधान:** GST का अधिरोपण वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है, जबकि इससे पूर्व कर वनिर्माण, बिक्री या सेवा प्रावधान पर अधिरोपित किये जाते थे।
- **अभिविधाय-आधारित प्रणाली:** GST अभिविधाय-आधारित उपभोग कर के रूप में कार्य करता है, जो पूर्व के मूल-आधारित कराधान मॉडल का स्थान लेता है।
- **बहुवधि कर स्लैब:** GST पाँच अलग-अलग दरों पर लगाया जाता है- 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जसमें GST परषिद द्वारा उत्पाद वर्गीकरण का निर्धारण किया जाता है।
- **दोहरी संरचना:** GST की दोहरी संरचना है, जहाँ केंद्र (CGST) और राज्य (SGST) दोनों एक ही लेनदेन मूल्य पर कर का अधिरोपण करते हैं।
 - वस्तुओं और सेवाओं के आयात को अंतरराज्यीय आपूर्ति माना जाता है और इस पर लागू सीमा शुल्क के अतिरिक्त IGST भी इसमें शामिल होता है।
- **शासन:** GST परषिद एक महत्वपूर्ण नरिणय लेने वाली संस्था है। माल एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) GST पोर्टल के लिये एक आईटी प्रणाली प्रदान करता है।
 - केंद्र और राज्य GST परषिद की अनुशंसाओं के आधार पर CGST, SGST और IGST दरें निर्धारित करते हैं।

वर्तमान GST ढाँचे में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **वस्तुओं का बहुविकरण:** पेट्रोलियम उत्पादों एवं मानव उपभोग हेतु शराब को अब भी GST के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप करों की दोहरावयुक्त प्रकृति (Tax Cascading) और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की अनुपलब्धता के कारण नकदी प्रवाह से जुड़ी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
 - जब राज्य **राज्य सूची की प्रवर्षिद 54** और **अनुच्छेद 366(12A)** के अंतर्गत **मूल्य वर्धति कर (VAT)** लगाते हैं, तब यदि इसे GST के तहत शामिल किया जाता है, तब **राजस्व हानि** और **राजकोषीय स्वायत्तता** को लेकर चिंताएँ उठती हैं।
- **माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) में वलिंब:** लंबे समय से लंबित **माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT)** को हाल ही में अधिसूचित किया गया है, फरि भी यह कई राज्यों में अभी भी क्रियाशील नहीं है। इसके कारण उच्च न्यायालयों में अपीलों की लंबित संख्या, नरिणय प्रक्रिया में लंबा वलिंब तथा करदाताओं के लिये अनश्चितता बनी हुई है।
- **जटिल कर दर संरचना:** वर्तमान में GST में पाँच प्रमुख कर स्लैब हैं, साथ ही 0.25%, 1% तथा 3% की वशिष दरें (मुख्यतः सोना, चाँदी और हीरे के लिये) लागू हैं। इससे वर्गीकरण संबंधी विवाद, बार-बार होने वाला वधिकि वाद-विवाद, तथा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले क्षेत्रों में कार्यशील पूँजी से जुड़ी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
 - हालाँकि मूल उद्देश्य तीन-दर प्रणाली को तार्ककि रूप देना था, लेकिन वशिषज्जों की सफिराशों और **GST परषिद** में हुई चर्चाओं के बावजूद इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।
- **प्रक्रियात्मक एवं अनुपालन संबंधी समस्याएँ:** स्वचालन और डिजिटलीकरण में प्रगति के बावजूद, प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जनिमें मामूली मुद्दों पर उच्च-मूल्य के मुकदमे, अत्यधिक नयिमन और बार-बार नयिमों में बदलाव के साथ जटिल अधिसूचनाएँ शामिल हैं।
- **वशिषज्जों का कहना है** कि ये प्रक्रियागत समस्याएँ प्रायः सरकार के सरलीकरण के व्यापक प्रयासों पर भारी पड़ती हैं।
- **व्याख्या संबंधी अस्पष्टताएँ:** GST के अंतर्गत मध्यस्थ सेवाओं, अंतर-कंपनी लेनदेन और कर्मचारी स्थानांतरण की व्याख्या में अस्पष्टता परपित्तों के बावजूद बनी हुई है, जिसके कारण अनुपालन में अस्पष्टता, परिचालन संबंधी बाधाएँ और व्यवसायों के लिये मुकदमेबाजी का जोखिम बढ़ रहा है।

वर्तमान GST ढाँचे में सुधार के लिये कौन-से सुधार लागू किये जा सकते हैं?

- **चरणबद्ध दृष्टिकोण:** पेट्रोलियम को शामिल करने के लिये चरणबद्ध दृष्टिकोण प्राकृतिक गैस और वमिानन टरबाइन ईंधन (ATF) के साथ शुरू हो सकता है, राजस्व-तटस्थ दर और राज्यों के लिये एक अस्थायी मुआवज़ा तंत्र का उपयोग करना, सुचारू एकीकरण सुनिश्चित करने के लिये एक वैध रणनीति है।

- जबकि **अनुच्छेद 366 (12A)** मानव उपभोग के लिये शराब को GST से बाहर रखता है, उच्च हस्तांतरण इस्सेदारी की पेशकश करके इसके समावेश को सुगम बनाया जा सकता है,
 - कम नरिभरता वाले राज्यों में पायलट परियोजनाएँ शुरू करना, तथा आम सहमत बनाने के लिये दीर्घकालिक राजकोषीय सुरक्षा प्रदान करना।
- **GST स्लैब दर का युक्तिकरण: उतकरमी शुल्क संरचना' (Inverted Duty Structure)** को दूर करने के लिये रफिंड प्रक्रिया में तेज़ी, इनपुट टैक्स (वशिषकर कृत्रिम रेशा - Man-made fiber) में पुनर्संतुलन, तथा मुआवज़ा उपकर (Compensation Cess) की पुनः समीक्षा की जानी चाहिये, जसिमें इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना या फरि उच्चतम GST स्लैब में समाहित करना शामिल हो सकता है।
- **वविाद समाधान प्रणाली को सशक्त करना:** लंबति अपीलों को उच्च न्यायालयों से शीघ्र नपिटाने और वरिधाभासी व्याख्याओं को रोकने के लिये GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) को पूरे देश में सक्रिय कयिा जाना चाहिये, जसिके लिये न्यायाधिकरणों में नयुक्तियों की प्रक्रिया को तीव्र कयिा जाना आवश्यक है।
- छोटे-मोटे मामलों पर मुकदमों को कम करने के लिये, प्रारंभिक प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर दंड को माफ करने के लिये एक **कषमा योजना** लागू कीजयिे और असपष्टताओं पर **अनवार्य परपित्तर** जारी कीजयिे।
- **डजिटल एकीकरण:** **जीएसटी नेटवर्क (GSTN)** को **आईसीईगेट (ICEGATE)**, वदिश व्यापार महानदिशालय (DGFT), भारतीय रजिर्व बैंक (RBI) और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) से जोड़ते हुए सगिल-वडिो अनुपालन प्रणाली लागू की जाये, जसिसे रयिल-टाइम डेटा साझा करने के साथ-साथ स्वतः-भरे गये रटिर्न की सुवधि प्राप्त हो सके।
- **AI आधारति जाँच प्रणाली** का उपयोग करते हुए रफिंड और ऑडिटि की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जाये, जैसे कनरियातकों को 15 दिनों के भीतर रफिंड दयिा जाना।
- **नये कषेत्रों में कर आधार का वसितार:** अगली पीढ़ी के GST सुधारों के तहत **करपिटो-एसेट्स**, **कार्बन करेडिट्स** एवं डजिटल वस्तुओं/सेवाओं जैसे उभरते कषेत्रों को स्वच्छ, एकरूप और वैश्विक मानकों के अनुरूप करना आवश्यक है।

नषिकर्ष

GST ने भारत के कर ढाँचे में एक बड़ा परिवर्तन कयिा है, जसिसेराजस्व में वृद्धि एवं आर्थिक औपचारकितता को बढ़ावा मलिा है। हालाँकि, **पेट्रोलियम उत्पादों की बहषिकृत, दरों की जटलिता और वविादों के समाधान में वलिंब** जैसी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। इन चुनौतियों से नपिटने के लिये आवश्यक है कर् **बहषिकृत कषेत्रों को चरणबद्ध रूप से शामिल कयिा जाये, कर दरों का सरलीकरण कयिा जाये, वविादों का शीघ्र समाधान सुनश्चिति कयिा जाये** तथा **डजिटल एकीकरण को सशक्त कयिा जाये**। ये सुधार GST प्रणाली को वास्तव में **"एक राष्ट्र, एक कर"** को सुनश्चिति करेगे और भारत के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को सशक्त आधार प्रदान करेंगे।

दृष्टाभुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. जबकि जीएसटी ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाया है, फरि भी इसकी संरचनात्मक और परिचालन संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।" इस कथन की समालोचनात्मक समीक्षा कीजयिे तथा सुधार हेतु उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न1. नमिनलखिति मर्दों पर वचिर कीजयिे: (2018)

1. छलिका उतरे हुए अनाज
2. मुरगी के अंडे पकाए हुए
3. संसाधति और डबिबाबंद मछली
4. वजिजापन सामग्री युक्त समाचार पत्तर

उपर्युक्त मर्दों में से कौन-सी वस्तु/वस्तुएँ जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतरगत छूट प्राप्त है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न2. 'वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्वसिज़ टैक्स/GST)' के करयिान्वति कयिे जाने का/के सर्वाधिक संभावति लाभ कया है/हैं? (2017)

1. यह भारत में बहु-प्राधिकरणों द्वारा वसूल कयिे जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाज़ार स्थापति करेगा।

2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर वदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु इसे सक्षम बनाएगा।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को वृहद् रूप से बढ़ाएगा और उसे नकित भवषिय में चीन से आगे नकिलने में सक्षम बनाएगा।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतपूरति) अधनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिये। कोवडि-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतपूरति निधि को प्रभावति कयिा है और नए संघीय तनावों को उत्पन्न कयिा है? (2020)

प्रश्न. उन अप्रत्यक्ष करों को गनिाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सम्मलिति कयिे गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रयिान्वति जीएसटी के राजसव नहितितार्थों पर भी टपिपणी कीजिये। (2019)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/8-years-of-gst>

